शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में इंतजार की घड़ी शीघ्र समाप्त करेगा स्कूल शिक्षा विभाग

अफसरों ने कहा जल्द होगी प्रक्रिया शुरू अभ्यार्थी बोले पहले पोर्टल पर पद प्रदर्शित करें विभाग | सफल उम्मीदवारों ने कहा कि संस्कृत और हिंदी जैसे विषय पदों की विभाग ने की है जमकर उपेक्षा

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

राज्य में लॉकडाउन के कारण बाधित हुई उच्च एवं माध्यमिक परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया अब शीघ्र प्रारंभ होगी। लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर शासन ने अनुमति दे दी है। अधिकारियों का कहना है कि इसी सप्ताह से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इधर सफल अभ्यर्थियों का फिर वही तर्क सामने आया है कि पहले विभाग भर्तियों में संशोधन करें। उच्च एवं माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा फरवरी-मार्च 2019 में आयोजित की गई थी। प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड के माध्यम से कराई गई, इस परीक्षा में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए 43 हजार 723 अभ्यर्थी सफल हुए थे। जबकि माध्यमिक शिक्षक परीक्षा में 2 लाख 16 हजार 241 उम्मीदवारों ने उत्तीर्ण की पात्रता हासिल की थी। इधर भर्तियों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने जो विज्ञप्ति जारी की है। उसमें 15000 उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर भर्तियां होना है। जबकि माध्यमिक शिक्षक के लिए 5 हजार 670 पद ही सृजित किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पदों की कमी को लेकर ही सफल अभ्यार्थी सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन उम्मीदवारों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में संस्कृत और हिंदी जैसे विषयों की विभाग को लगता है चाहत नहीं है। जबकि प्रदेश भर में इन दोनों ही विषयों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इस बात की है कि विभाग ने पोर्टल पर यह पद प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं समझी है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा में अंग्रेजी विषय को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है।

शीघ्र ही होगी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ: गौतम सिंह

लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक गौतम सिंह का कहना है कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होने की उम्मीद है। इसके लिए शासन को जो फाइल भेजी गई थी। अनुमोदित होकर आने वाली है। श्री सिंह का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और आरटीई के मापदंडों को ध्यान में रखकर की जा रही है। प्रक्रिया में विसंगतियों के आरोपों से संबंधित कुछ ज्ञापन आए थे। लेकिन विभाग का जो नियम है उसी से संबंधित भर्तियां की जाएंगी। पहले से जितने पद हैं। उसी के अनुसार भर्तियां होंगी। लोक शिक्षण संचालनालय के डायरेक्टर गौतम सिंह के अनुसार गणित और विज्ञान की ज्यादा जरूरत है। इन विषयों में दक्ष शिक्षकों की भर्ती करना हमारी प्राथमिकता है।

शासकीय स्कूलों में स्थाई शिक्षकों की भारी कमी: रंजीत

भर्तियों में पारदर्शिता की लड़ाई लड़ रहे सफल उम्मीदवार रंजीत गौर का कहना है कि प्रदेश के शासकीय स्कूलों में स्थाई शिक्षकों की भारी कमी है। खासकर माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा में संस्कृत और हिंदी जैसे विषयों के पदों कि विभाग द्वारा उपेक्षा की गई है। स्थाई शिक्षकों की पूर्ति के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए फरवरी-मार्च 2019 में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की थी। जनवरी 2020 में उच्च एवं माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति व प्रावधिक सूची भी जारी कर दी गई थी परन्तु अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।

शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में पदों को छुपाया गया है : पूजा

उत्तीर्ण उम्मीदवार पूजा सिंघल का कहना है कि भारत के अन्य कई राज्यों में सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए स्थाई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है परंतु मध्यप्रदेश में ही स्थाई शिक्षक भर्ती अभी तक अटकी हुई है। इनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया शुरुआती दौर से विसंगति पूर्ण रही है। अंग्रेजी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। जबकि माध्यमिक शिक्षक भर्ती में संस्कृत और हिंदी जैसे विषयों के पदों पर ध्यान देना जरूरी था। इन विषयों के कितने पद रिक्त है। अधिकारियों ने कभी भी सही जानकारी नहीं दी है। प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों में सालों से यह पद रिक्त पड़े हुए हैं। सफल अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए मुख्यमंत्री, स्कूल सचिव व आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय आदि को कई बार ज्ञापन पत्र सौंप चुके हैं। इन सब के बावजूद भी अभी स्थाई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है।

रखनी होगी भर्ती प्रक्रिया पर नजर

परीक्षा में सफल अभ्यर्थी रोहित चौधरी का कहना है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को जल्द प्रारंभ कर मुख्यमंत्री को नजर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि विभाग ने पहले से स्कूलों में विषय वार खाली पद प्रदर्शित नहीं किए। इस कारण यह प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। शासकीय स्कूलों में स्थाई शिक्षकों की भारी कमी है। पिछले कई वर्षों से अतिथि शिक्षकों द्वारा ही बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है स जबकि विभाग कह रहा है कि पदों की कमी है। अतिथियों द्वारा सेवाएं देना सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रदेश के स्कूलों में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं। उन्होंने मांग उठाई है कि विभाग को तत्काल खाली पदों की जानकारी पोर्टल पर डालनी चाहिए। ताकि प्रदेश की जनता इस हकीकत को देख सके।

खाली पदों की संख्या पोर्टल पर डलवाएं

परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ममता निगम का कहना है कि सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री विषय वार खाली पदों की संख्या विभाग के पोर्टल पर डलवाएं। ताकि उम्मीदवार को यह पता चल सके कि किस विषय के कितने पद रिक्त हैं। आरोप लगाया गया है कि शुरू से ही मांग उठाने के बावजूद विभाग के अधिकारियों ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों के पदों को भरने पर विभाग का पूरा ध्यान है। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सहित अन्य अधिकारी एवं मंत्रियों से मांग की है कि भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में संशोधन के बाद स्थाई शिक्षक भर्ती समय पर पूर्ण हो एवं समस्त रिक्त पदों पर न्याय पूर्ण भर्ती हो। जिससे अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके।

वेबसाइट ssc.nic.in पर नोटिस जारी

कर्मचारी चयन आयोग की पेंडिंग परीक्षाओं का आया शेड्यूल

जेएनएन, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग ने कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति की समीक्षा करने के बाद पेंडिंग परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। एसएससी ने नए एग्जाम शेड्यूल के संबंध में एक नोटिस अपनी वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी किया है। इस नोटिस में कई परीक्षाओं का शेड्यूल दिया गया है। बता दें कि परीक्षा का शेड्यूल मौजूदा स्थितियों के अधीन है और यह समय-समय पर जारी सरकारी दिशा निर्देशों पर निर्भर करता है। उम्मीदवारों को आगे के अपडेट के लिए समय-समय पर आयोग की वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

आपदा के बीच कर्मचारियों ने उठाया आंदोलन का झंडा

कर्मचारी कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

भोपाल। लॉकडाउन जरूर चल रहा हो लेकिन अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन पर उतरने लगे हैं। कर्मचारी कांग्रेस ने जहां सोमवार को विंध्याचल भवन में प्रदर्शन किया। वही मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने गृह मंत्री को सड़क पर रोक कर ज्ञापन दिया।सातवें वेतनमान का लंबित एरियर सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी कांग्रेस ने दोपहर वक्त विंध्याचल भवन पर प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र ने कहा कि मौजूदा सरकार शासकीय सेवकों की सुविधाओं में निरंतर कटौती कर रही है। शिक्षकों से लेकर अन्य विभागों के कर्मचारी आपदा के समय जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। संगठन के प्रमुख पदाधिकारी आदर्श शर्मा एनके नामदेव सहित अन्य ने बताया कि सरकार कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं कर रही है।

शिक्षकों ने मांगा पदोन्नति पदनाम

मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा प्रदेश के प्रांतीय पदाधिकारियों की ऑनलाइन मीटिंग ली गई। इस दौरान संगठन की मजबूती और चुनाव सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में सहमति बनी कि तत्काल मुख्यमंत्री से भेंट कर शिक्षकों को पदोन्नति पदनाम देने की मांग की जाएगी। कोरोना कार्य में लगे सभी शिक्षकों को योद्धा का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन के प्रदेश महामंत्री छत्रवीर सिंह राठौर ने बताया कि अन्य विषयों पर भी मीटिंग में चर्चा हुई।

ऑनलाइन पढ़ाई • फीडबैक में हुआ खुलासा, ऐसे मामलों में टॉपर विद्यार्थियों को नोट्स भेजकर पढ़ाई करा रहा शिक्षा विभाग

9वी-12वीं के 86 हजार में से 20 हजार विद्यार्थियों के पास मोबाइल व टेलीविजन की सुविधा ही नहीं

भास्कर संवाददाता | सागर

लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को ऑनलाइन पद्धति से पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा तमाम प्रयास किए गए हैं। इसके तहत एंड्रायड मोबाइल के अलावा केबल नेटवर्क और दूरदर्शन पर भी शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बावजूद जिले के 20 हजार से ज्यादा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास दूरदर्शन तक की सुविधा नहीं है। यह खुलासा विभाग द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गए फीडबैक से हुआ है। विभाग इन विद्यार्थियों को पुराने टॉपर विद्यार्थियों के नोट्स भेजकर पढ़ाई करा रहा है।

जिला शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई के साथ-साथ शिक्षकों से इस पद्धति का फीडबैक भी कराया है। जिले में करीब 300 मॉनीटरों द्वारा लिए गए फीडबैक में सामने आया है कि जिले में मौजूद कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 86015 विद्यार्थियों में से 20842 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास एंड्रायड मोबाइल और केबल नेटवर्क तो दूर दूरदर्शन देखने तक की व्यवस्था नहीं है। फीडबैक में इस बात का खुलासा होने के बाद शिक्षकों ने इन विद्यार्थियों के लिए पुराने टॉपर छात्र-छात्राओं के नोट्स फोटोकॉपी कराकर भेजे हैं। ताकि वे लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई से वंचित नहीं रहें। ऐसे छात्र कुल विद्यार्थियों का 24 फीसदी हैं।

इस संबंध में तैयार कराई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के पहले चरण के बाद से ही जिले में ऑनलाइन पढ़ाई की शुरूआत कर दी गई थी। लॉकडाउन पहले से चौथे चरण तक आते-आते ऑनलाइन पढ़ाई में काफी बदलाव हुआ है।

फैक्ट फाइल

- 86015 विद्यार्थी कुल जिले में
- 31346 विद्यार्थी पढ़ रहे मोबाइल से
- 4706 विद्यार्थियों को केबल नेटवर्क से पढ़ाया जा रहा
- 29116 विद्यार्थी पढ़ रहे दूरदर्शन पर
- 20842 विद्यार्थियों के पास कोई संसाधन नहीं

पहले केवल एंड्रायड मोबाइल पर वाट्सएप के जरिए विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था। अब टेलीविजन के जरिए केबल नेटवर्क और दूरदर्शन पर भी कक्षावार अलग-अलग समय पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है।

जिले 36 फीसदी मोबाइल व कुल 75.76 फीसदी पढ़ रहे ऑनलाइनः जिले में 36.44 फीसदी विद्यार्थी मोबाइल के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों को रोज डिजीलेप वाट्सएप ग्रुप पर शैक्षणिक सामग्री तथा वीडियो भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा कुल 39.32 फीसदी विद्यार्थी केबल टीवी और दूरदर्शन पर पढ़ाई कर रहे हैं। विभाग के अनुसार कुल 75.76 फीसदी विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़ लिया गया है।

लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों ने अपने-अपने स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियों को बनाए रखने के प्रयास किए हैं। कई शिक्षकों ने छात्रों को पाठ्य सामग्री भेजी है। जिले से की गई मॉनिटरिंग में सामने आया कि कई स्थानों पर शिक्षक छात्र मित्र बनाकर भी शैक्षणिक कार्य करा रहे हैं। इसके साथ ही स्मार्ट क्लास के जरिए भी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

कुछ विद्यार्थियों के साथ परेशानी है, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकी

डॉ. महेंद्र प्रताप तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी सागर का कहना है कि जिले में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का संचालन करने के लिए 1136 शिक्षकों को तैनात किया गया है। कुल 324 शालाओं के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग कक्षावार 1035 वाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। जिले के कुछ स्थानों पर विद्यार्थियों के पास मोबाइल, केबल नेटवर्क तथा दूरदर्शन की सुविधा नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों को पुराने टॉपर छात्रों के नोट्स उपलब्ध कराकर पढ़ाई के लिए प्रेरित किया गया है। अकादमिक सेल से सप्ताह में 3 दिन पाठ्य सामग्री व 3 दिन मॉनीटरिंग करने के साथ रोज 5 विद्यार्थियों से बात कर फीड बैक लिया जा रहा है।

भास्कर एक्सपर्ट पैनल से जानिए कैसा हो सकता है शिक्षा सत्र

तीन शिफ्ट में लगे स्कूल, हालात सामान्य होने तक नर्सरी से 5वीं तक की छुट्‌टी रहे

शहर की दुकानें खुलीं, अब स्कूल खोलने पर चिंतन

भास्कर संवाददाता | उज्जैन

कोरोना संक्रमण के बीच इस साल स्कूल-कॉलेजों में नया सेशन देरी से तो शुरू होगा लेकिन उसके बाद स्कूल-कॉलेजों में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी की जाएगी, जो पहले कभी देखी और सुनी नहीं गई।

केंद्र और राज्य स्तर से हो रही तैयारियों के साथ ही भास्कर ने शिक्षाविदों की एक्सपर्ट पैनल के साथ यह जाना कि आखिर नए सत्र में क्या कुछ बदलाव शिक्षा जगत में होंगे। एक्सपर्ट पैनल की मानें तो पहली बार स्कूलों में दो से तीन शिफ्ट में कक्षा संचालन किया जा सकता है। इसके अलावा ईवन-ऑड (सम-विषम) या नंबरिंग के आधार पर विद्यार्थियों को स्कूल में अलग-अलग दिन बुलाया जा सकता है। केंद्र स्तर पर भी स्कूल खोलने की तैयारियां की जा रही हैं लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि कक्षाओं का संचालन किस तरह किया जाए? केंद्र की तैयारियों के साथ ही भास्कर के एक्सपर्ट पैनल पैनल से जानते हैं कि आखिर क्या होगा स्कूल-कॉलेज में आने वाले शिक्षा सत्र का दृश्य।

50 या 33% विद्यार्थियों की उपस्थिति, बाकी दिन ऑनलाइन पढ़ाई

▪ 1 दिन में 33% या 50% विद्यार्थी ही स्कूल जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो 50% का फॉर्मूला लागू करने वाले स्कूलों में विद्यार्थी सप्ताह में 3 दिन और 33% का फॉर्मूला लागू करने वाले स्कूल में विद्यार्थी 2 दिन स्कूल जाएंगे। बाकी दिन ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ▪ 15 जुलाई के बाद स्कूल खोलने की तैयारी है। नए सत्र में फीस नहीं बढ़ाएंगे। ▪ संसाधनों के आधार पर राज्य सरकार और स्कूल प्रशासन तय करेंगे कि कितने बच्चे स्कूलों में हर दिन बुलाना है। ▪ विद्यार्थी संख्या के आधार पर स्कूल में पीने के पानी, हाथ धोने की सुविधा, टॉयलेट आदि की व्यवस्थाएं होंगी और इन सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। ▪ छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ▪ हर शिफ्ट के बाद और पहले स्कूल एवं कक्षाओं को सैनिटाइज किया जाएगा। ▪ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शिक्षकों के साथ स्कूल स्टाफ को इसके लिए ट्रेनिंग सेशन भी रखे जाएंगे। ▪ बस और ऑटो में स्कूल आने-जाने वाले विद्यार्थियों के लिए संख्या तय की जाएगी।

एक्सपर्ट पैनल ने सुझाए 5 बिंदु

1 छोटे बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग को बेहतर तरीके से नहीं समझते। इसलिए प्रथम चरण में छठवीं से अधिक कक्षाओं का ही संचालन किया जाए और नर्सरी से पांचवीं तक की कक्षाओं में स्थिति सामान्य होने तक अवकाश रखा जाए।

2 ऑनलाइन पढ़ाई का पैटर्न बढ़ रहा है इसलिए न्यूनतम उपस्थिति के मापदंडों में ऑनलाइन उपस्थिति को भी शामिल किया जाए। ताकि कोई भी विद्यार्थी 75% से कम कक्षा में उपस्थिति होने पर परीक्षा से वंचित न रह सके।

3 फिलहाल यह तय नहीं है कि कब से स्कूल शुरू होंगे। सेशन लेट होगा इसलिए स्कूलों का कोर्स भी केवल सत्र 2020-21 के लिए कुछ कम किया जाए। इसे 75% तक रखा जा सकता है।

4 ऐसी व्यवस्था भी हो कि जिस दिन विद्यार्थी स्कूल न जाए तो भी वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सके।

5 प्रार्थना सभाओं को कक्षाओं में समेटा जा सकता ताकि डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।

छुट्टियां कम, ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करें

अगस्त-सितंबर से पहले सेशन शुरू होने की संभावनाएं कम है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन अटेंडेंस के फॉर्मूले को लागू किया जा सकता है। **डॉ. अलका व्यास**, पूर्व डिप्टी सेकेटरी (यूजीसी) और विभागाध्यक्ष विक्रम विवि

स्कूल स्तर पर ही तैयार करना होगा ई-लर्निंग

छोटी कक्षाओं में शिक्षकों का दायित्व हो जाएगा वे विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंस, मास्क और खुद को सैनिटाइज जैसे नियम स्वतः अपनाएं। स्कूलों को ई लर्निंग की ओर जाना पड़ेगा। **डॉ. संदीप नाडकर्णी**, व्याख्याता, शा. शिक्षा महाविद्यालय

गैरजरूरी पाठ व परीक्षा की संख्या कम की जाए

इस बार सेशन आगे बढ़ेगा। सत्र 2020-21 के लिए स्कूली स्तर पर कक्षाओं में कुछ चैप्टर एक साल के लिए कम किए जाना चाहिए ताकि सिलेबस समय पर पूरा हो सके। परीक्षाओं की संख्या हाई और हाई सेकेंडरी स्तर पर कम की जा सकती हैं। **भरत व्यास**, प्राचार्य शाउमावि

बीएचईएल स्थित कार्मल कांवेंट स्कूल का मामला पहुंचा बाल आयोग

प्रबंधन ने कहा, 5 जून तक जमा करें फीस नहीं तो ऑनलाइन स्टडी ग्रुप से हटा देंगे

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

राजधानी में निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। फीस को लेकर शासन के आदेश के बाद भी कई स्कूल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला बीएचईएल स्थित कार्मल कांवेंट स्कूल का सामने आया है। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों से 5 जून तक स्ट्रीम अलॉटमेंट फीस जमा करने को कहा है। यह भी निर्देश दिया कि जो स्टूडेंट फीस नहीं जमा करेंगे तो उसे ऑनलाइन स्टडी ग्रुप से बाहर कर देंगे।

खास बात

- आयोग ने डीईओ को लिखा पत्र, डीईओ कर रहे कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी

आदेश का नहीं हुआ पालन

शासन के आदेश अनुसार ना तो 30 जून के पहले अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा सकता है और ना ही ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई फीस ली जा सकती है। स्कूल द्वारा जारी निर्देश में शासन के आदेश की अवमानना की गई है। हमने स्वत: संज्ञान लेकर डीईओ को अवगत कराया है।

ब्रजेश चौहान, सदस्य, बाल आयोग

नियमानुसार की जाएगी कारवाई

बाल अधिकार संरक्षण की तरफ से हमें स्कूल की शिकायत मिली है। संबंधित स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा और जवाब मिलने के बाद नियमानुसार कारवाई की जाएगी।

नितिन सक्सेना, जिला शिक्षा अधिकारी

बाल आयोग ने शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के लिए कहा

जानकारी बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक पहुंचने के बाद आयोग ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की है। आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक कॉर्मल कांवेंट स्कूल द्वारा ग्यारहवीं कक्षा के स्टूडेंट के ग्रुप में स्कूल द्वारा फीस जमा करने संबंधी मैसेज भेजा गया था। इसमें 30 मई से 5 जून के बीच स्टूडेंट को स्ट्रीम अलॉटमेंट फीस के रूप में 3000 रुपए जमा करने के निर्देश दिए गए थे। यह भी कहा गया था कि 6 जून से उन स्टूडेंट के लिए जो फीस जमा कर चुके एडमिशन फॉर्म उपलब्ध होंगे और एडमिशन लेने की अंतिम तारीख 10 जून होगी।

प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों में 4 लाख विद्यार्थी देंगे यूजी-पीजी के अंतिम वर्ष की परीक्षा

प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों में स्नातक (यूजी) अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर (पीजी) चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं पेन-पेपर मोड पर 29 जून से 31 जुलाई के मध्य आयोजित होंगी। इसके तहत 7 विश्वविद्यालयों में लगभग 4 लाख विद्यार्थी स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं देंगे। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने बताया कि कुल 597 परीक्षा केन्द्रों पर स्नातक अंतिम वर्ष के लगभग 3 लाख 4 हजार 853 विद्यार्थी तथा स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर के लगभग एक लाख विद्यार्थी आफलाइन परीक्षा में शामिल होंगे। प्रमुख सचिव ने बताया कि स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर और अन्य पाठ्यक्रमों की नियमित परीक्षाएं स्थानीय स्तर पर परिस्थितियां सामान्य होने पर आयोजित की जा सकेंगी। स्नातक कक्षाओं के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष सेमेस्टर का एक सितंबर 2020 से नया सत्र प्रारंभ किया जाएगा।

6 विवि ने स्नातक स्तर की 25 प्रतिशत परीक्षाएं पहले ही हो गई : राजन ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा विश्वविद्यालय को छोड़ कर शेष 6 विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर की 25 प्रतिशत परीक्षाएं हो गई है। स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाएं किसी भी विवि में नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन में परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

12वीं की परीक्षा देने विद्यार्थियों को 1 घंटे पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की बारहवीं परीक्षा में विद्यार्थियों को एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। थर्मल स्कैनिंग के बाद केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। सोमवार को मंडल ने परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के लिए निर्देश जारी किए है। माशिमं के जारी निर्देशों में कहा गया है कि परीक्षा केंद्र में भेजने से पहले अभिभावक सुनिश्चित करेंगे कि उनका बच्चा बीमार तो नहीं है। परीक्षा केंद्र पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र पर सुबह की पाली में 8 बजे व दोपहर की पाली में एक बजे विद्यार्थियों को पहुंचना होगा। परीक्षा के एक घंटे पहले पहुंचने पर छात्रों की थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जाएगा।

परीक्षा प्रारंभ होने के दस मिनट पहले कापियां दी जाएगी। पांच मिनट पहले प्रश्न-पत्र दिए जाएंगे। परीक्षा केंद्र में सुबह 8:45 व दोपहर में 1:45 के बाद आने वाले किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बता दें कि मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की बारहवीं की शेष परीक्षा का टाइम टेबिल पूर्व में घोषित चुका है।

अध्यापकों के लंबित एरियर्स भुगतान कराये जाने की मांग

जवा ब्यूरो। प्रदेश के अध्यापक संवर्ग को शासन के निर्देशों के अनुक्रम में छठवे वेतनमान का एरियर्स तीन किस्तों में देने संबंधी आदेश जारी किये गए थे। जिसके तहत तृतीय किस्त का एरियर्स अप्रैल पेड मई 2020 में भुगतान होना था, लेकिन विकासखण्ड जवा के संकुल प्राचार्यो की हठधर्मिता के कारण अभी तक बिल कोषालय में प्रस्तुत नही किये गये। उक्ताशय की जानकारी देते हुए आजाद अध्यापक शिक्षक संघ रीवा के संभागीय प्रवक्ता पुष्पेंद्र द्विवेदी ने बताया कि विकासखण्ड जवा के संकुल केंद्र बरहुला, पनवार, डभौरा, पुरौना सहित कई संकुलों में अध्यापकों के छठवे वेतन की तृतीय किस्त के एरियर्स का बिल विकासखंड शिक्षा अधिकारी जवा को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाना था, जो अभी तक नही किया गया है। हजारों अध्यापक एरियर्स को लेकर परेशान होकर संकुलों का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। सूत्रों के अनुसार ज्ञात हुआ है कि कुछ संकुलों में बैठे दलाल लेनदेन की आस लगाए बैठे हैं इसलिय समय पर बिल लगाने में हीला हवाली की जा रही है। अध्यापक राजेश सिंह, संजय सिंह, राजेंद्र सिंह चौहान, हरीलाल वर्मा, अतुल दुबे, प्रमोद चतुर्वेदी, सतेंद्र त्रिपाठी, दयाशंकर मिश्रा, धर्मराज वर्मा, दयानंद द्विवेदी, अभयराज कोरी, ज्ञान सिंह, रामसुमेर वर्मा, अशोक पांडेय, लालता प्रसाद आदि ने कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लंबित एरियर्स का भुगतान कराए जाने की मांग की है।

परीक्षा-केन्द्र पर विद्यार्थी एक घंटे पूर्व उपस्थित होंगे

भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम की स्थगित परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाने के क्रम में विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्रों पर एक घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा। परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व सभी विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी।

पैरेंट्स की समझाइश को किड्स कर देते हैं नजरअंदाज

इंटरटेनमेंट के साधन बच्चों पर हावी

सिटी रिपोर्टर . सतना

आधुनिकता के दौर में इटरटेनमेन्ट बच्चों में इस कदर हावी हो चुका है की एक घर में जितने बच्चे होते है सबकी च्वाइस अलग-अलग होती है। आज टीवी में सीरियल ,कॉमेडी शो, के साथ कार्टून आते हैं जिन्हे बच्चे खुब पसंद कर रहे हैं। बच्चों में ज्यादातर आदत यह होती है की वह खाना खाते समय टीवी देखते है जिसके चलते वह अपने पैरेंट्स की बातों को अनसुना कर देते हैं बल्कि टीवी देखते हुए खाना खाने की वजह से मोटापे का भी शिकार हो सकते हैं। चिकित्सकों की माने तो टीवी देखते हुए खाना खाने की वजह से बच्चे अपनी डाइट से कहीं ज्यादा फूड खा लेते हैं जिसकी वजह से फैट एकत्र होने लगता है। यही नहीं ज्यादा समय तक टीवी में खोए रहने वाले किड्स आउट डोर गेम्स भी खेलने से परहेज करने लगते हैं और उनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी कम होने लगती है जो उनके बढ़ते हुए शरीर के विकास के लिए खतरनाक हो सकता है।

टीवी बन रही परेशानी

एक घंटा हो गया और अभी तक तुम्हारा खाना खत्म नहीं हुआ। कितनी बार कहा है कि खाते समय टीवी मत देखा करो पर नहीं टीवी के बिना तो निवाला अंदर ही नहीं जाता है। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का भन्नाती हुई रानी ने लाइट का मेन स्विच ऑफ कर दिया। उधर बेटा राहुल ने टीवी बंद हो जाने से गुस्से में खाने की प्लेट को ही गिरा दिया। रानी ने आव देखा न ताव और टीवी को उठा कर पटक दिया यह कह कर कि सारी समस्या की जड़ यही है न। ऐसी परेशानी हर घर की हो रही है। यह समस्या सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि आज हर घर की है भले ही टीवी हर घर में न टूटता हो। पर खाना खाते समय टीवी जरूर ऑन रहता है खास कर जब बच्चे खाना खा रहे होते हैं।

बीमारियों का कारण टीवी

टीवी देखते समय खाना खाते-खाते वही बच्चा स्वस्थ न होकर उल्टा मोटापे का शिकार हो जाता है। वजह कि बच्चा टीवी देखते-देखते जरूरत से ज्यादा खा लेता है और खाता ही जाता है। स्नैक्स और फ स्टफूड जैसी चीजें भी टीवी देखते समय बच्चे खूब चाव से खाते हैं और ज्यादा खाते हैं। यही आदत बच्चों को शारीरिक रूप से भारी-भरकम बना देता है जो आगे चल कर कई बीमारियों का कारण बनता है।

खाने में नहीं रहता ध्यान

टीवी हमें काफी पैसिव बनाता है करना कुछ भी नहीं होता जो स्क्रीन पर परोसा जाएगा उसका हमें उपभोग करना होता है। यदि कार्यक्रम मनोरंजक हो तो खाना खाने जैसी समानांतर गतिविधि से ध्यान हट जाता है।

क्या करें पैरेंट्स

- समय-समय पर टीवी देखने को कहें।
- इस टाइम पास के लिए हो टीवी का देखना
- टीवी देखने के अच्छाई और बुराई की करें चर्चा
- खाते वक्त टीवी देखने में लगाएं रोक
- अच्छे सीरियल और मनोरंजक चीजों से पढ़ाएं प्रेरणा का पाठ
- आउट डोर गेम्स को दे बढ़ावा
- हो सके तो खुदका समय दे बच्चों को।

जेईई, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स एप से दे सकेंगे मॉक टेस्ट

धार | मानव संसाधान विकास मंत्रालय ने जेईई मेन, नीट सहित अन्य कॉम्पटीटिव एक्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एप लांच किया है। इससे प्रतिभागी ऑनलाइन मॉक टेस्ट देकर तैयारी का आकलन कर सकते हैं। इसका नाम "नेशनल टेस्ट अभ्यास' एप है। इस संबंध में एनटीए की ओर से एक सूचना जारी की गई है।

नए शिक्षक संवर्ग के हजारों अध्यापकों को भी मिलेगा एचआरए और सीसीए

आईएफएमआईएस पोर्टल से जारी होगा वेतन, 572 को एम्प्लाई कोड जारी

इंदौर • डीबी स्टार

नए शिक्षक संवर्ग के हजारों अध्यापकों को एचआरए (होम रेंट अलाउंस) और सीसीए (सिटी कन्वेंस अलाउंस) मिलेगा। शिक्षा विभाग ने अफसरों को केवायसी अपडेट करने के आदेश दिए हैं। इंदौर में 572 शिक्षकों के एम्प्लाई कोड जारी किए हैं। उन्हें मई का वेतन इंटिग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल से मिलेगा।

नियमित शिक्षकों प्राचार्यों का वेतन आईएफएमआईएस और अध्यापकों का वेतन शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल से जारी होता है। शिक्षक मांग कर रहे थे कि उनका वेतन भी आईएफएमआईएस से निकाला जाए।

पोर्टल से ऐसे जुड़ेंगे शिक्षक

शिक्षा विभाग ने एजुकेशन पोर्टल पर ई-केवायसी के लिए लिंक जारी की है। शिक्षक इसमें जानकारी भरकर फॉर्म सब्मिट करेंगे। इस डाटा को संकुल प्राचार्य वेरिफाई कर डीडीओ (बीईओ) को भेजेंगे। बीईओ ई-केवायसी अपडेट कर ट्रेजरी को भेजेंगे, जहां से कर्मचारियों के एम्प्लाई कोड जारी होंगे। कोड जारी होते ही शिक्षक आईएफएमआईएस पोर्टल से जुड़ेंगे। जिला कोषालय की ट्रेजरी ऑफिसर प्रगति जैन का कहना है कि डीडीओ ने हमें 572 शिक्षकों का डाटा भेजा है। हमने इनके एम्प्लाई कोड जारी किए हैं। अब आईएफएमआईएस पोर्टल से ही इनका मई का वेतन निकलेगा।

71 करोड़ रुपए नहीं मिले थे

कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश के कई कर्मचारी संगठनों ने कर्मचारियों के वेतन से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया था। नियमित कर्मचारियों का डाटा आईएफएमआईएस पोर्टल पर होने से सभी कर्मचारी-अफसरों का वेतन कट कर सीधे कोष में जमा हो गया था। नवीन शैक्षणिक संवर्ग के अध्यापकों का डाटा पोर्टल पर नहीं होने से उनके अंशदान के करीब 71 करोड़ सरकार को नहीं मिले थे। डीबी स्टार ने यह मामला अपने 14 अप्रैल के अंक में प्रमुखता से उठाया था। बाद में शिक्षकों ने अपने स्तर पर अंशदान की कोष में जमा कराई थी।

शिक्षकों ने विद्यार्थियों को वितरित की मध्याह्न भोजन योजना की खाद्य सामग्री

बांगरदा | ग्राम की प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शासकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षकों ने खाद्यान्न का वितरण घर-घर जाकर किया। छात्र-छात्राओं ने बताया शासन ने मध्याह्न भोजन योजना की राशि उनके बैंक खाते में जमा कर दी है। इस दौरान जनशिक्षक बिहारीलाल रेवापाटी, प्रधानाध्यापक अशोक सिंह पंवार,

संतोष मालाकार, प्राचार्य लक्ष्मण पुनसिया उपस्थित थे।

बीयू ने जारी की परीक्षाओं की संशोधित समय सारणी

भोपाल (आरएनएन)। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की संक्रमण के कारण स्थगित की गई परीक्षाओं की संशोधित समय सारणी जारी कर दी गई है। जिसके अनुसार बीयू की बची हुई परीक्षाएं 29 जून से प्रारंभ होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बीयू प्राइवेट स्कूलों को परीक्षा केंद्र बना सकता है। वहीं कंटेनमेंट एरिया में बनी परीक्षाकेंद्रों में भी बदलाव किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रबंधन के अनुसार आसपास के गांवों में रहने वाली परीक्षार्थियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए जो विद्यार्थी जहां रहता है उसी के आसपास के 2 से 3 किलोमीटर के क्षत्र में परीक्षा केंद्र बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बीयू द्वारा जारी टाइम टेबल के अनुसार यूजी के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 29 जून से प्रारंभ होकर 18 जुलाई को समाप्त हो जाएंगी।

यूजी की परीक्षाएं तीन पालियों में संचालित होंगी। वहीं पीजी के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 4 जुलाई से शुरू होंगी जो 14 जुलाई को समाप्त हो जाएंगी। पीजी की परीक्षाएं एक ही पाली में संचालित होंगी। विश्वविद्यालय प्रबंधन के मुताबिक परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ विद्यार्थियों की परीक्षा फॉर्म जमा नहीं हो सके हैंए इसलिए विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म परीक्षा शुरू होने के 1 दिन पहले तक स्वीकृत किए जाएंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल करने के लिए प्रथक से पत्र भेजा जाएगा ताकि कोई भी विद्यार्थी परीक्षा से वंचित नहीं रह सके।

प्रश्नों की संख्या होगी कम: विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक कोरोनावायरस को देखते हुए फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना है इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा का समय 3 घंटे की जगह 2 घंटे करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। परीक्षा का समय कम करने के साथ ही प्रश्नों की संख्या भी कम की जाएगी।

निजी स्कूल संचालकों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा

स्टेशनरी, यूनीफॉर्म के लिए बनाया दबाव तो धारा 188 के तहत कार्रवाई

सतना। नवीन शिक्षण सत्र को लेकर निजी विद्यालयों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कलेक्टर ने सोमवार को स्कूल संचालन, ड्रेस, स्टेशनरी और फीस संबंधी निर्देश जारी किए हैं। अगर निजी विद्यालय संचालक छात्रों या अभिभावकों पर निजी प्रकाशकों की किताब या फिर किसी एक जगह से यूनीफार्म खरीदने का दबाव बनाता है तो उसके विरुद्ध धारा 188 और दुकान संचालक के विरुद्ध धारा 120 बी के तहत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने 11 बिन्दुओं के निर्देश जारी किए गए है। जिसमें स्कूलों की तैयारियों सहित बच्चों से ली जाने वाली फीस का जिक्र है। उल्लेखनीय है कि, नवीन सत्र की पढ़ाई के लिए फीस वृद्धि पर प्रदेश सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई थी।

» न फीस बढ़ा सकेंगे और न एकमुश्त जमा करने का दबाव बनाएंगे

» अभिभावक सुविधानुसार चार किश्तों में भी जमा कर सकते हैं

नहीं ले सकेंगे विलंब शुल्क

स्पष्ट किया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 में जिन छात्रों की फीस जमा नहीं हो सकी थी उनसे विलंब शुल्क लिए बिना फीस जमा की जाएगी। यह अवधि 30 जून तक है। नवीन सत्र 2020-21 में अशासकीय विद्यालय शुल्क वृद्धि नहीं कर सकेगा। अभिभावकों को एकमुश्त फीस जमा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। उनकी सुविधा अनुसार प्रति माह फीस जमा करने की छूट होगी। या फिर न्यूनतम चार किश्तों में फीस ली जा सकती है। ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर अतिरिक्त शुल्क ट्यूशन फीस के अलावा नहीं ली जा सकती।

नियमित स्वास्थ्य परीक्षण

कलेक्टर ने निजी विद्यालय संचालकों को निर्देश दिए हैं कि, कोविड-19 के खतरे को देखते हुए विद्यालय में पर्याप्त पानी, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। छात्रों को चेहरा मास्क से ढंकने के लिए प्रेरित करें। विद्यालय में अग्निशमन यंत्र एवं पानी पर्याप्त रखें। यह निर्देश सीबीएसई,आईसीएसई,माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल तथा अन्य बोर्डों के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए हैं। नियमों के उल्लंघन पर संबंधितों के खिलाफ मान्यता नियमों के तहत कार्रवाई होगी।

फीस को लेकर कलेक्टर सर द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव बनाने वाले निजी स्कूल प्रबंधनों पर अंकुश लगाने की हिदायत दी गई है।

टीपी सिंह, डीईओ सतना

जारी हुए 212 शिक्षकों के क्रमोन्नति आदेश

अशोकनगर, ब्यूरो। जिले भर में 212 प्राथमिक शिक्षकों के क्रमोन्नति आदेश लंबे समय से रुके हुए थे। जिन्हे बीते दिनों जारी कर दिया गया है। आजाद अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष भीम सिंह यादव ने बताया कि इस संबंध में संघ द्वारा सांसद डॉ. केपी यादव से संपर्क किया गया था, जिसके बाद उन्होंने निराकरण का आश्वासन दिया था। आदेश जारी होने के बाद संघ के सदस्यों ने सांसद का आभार व्यक्त किया और माध्यमिक शिक्षकों के क्रमोन्नति हेतु एवं रुके हुए साथियों के संविलियन की समस्याएं भी साझा कीं। जिलाध्यक्ष श्री यादव ने बताया कि इस आदेश से शिक्षकों को 3 हजार रुपए तक का मासिक लाभ होगा, हालांकि यह आदेश एक वर्ष पहले हो जाना थे क्योंकि उक्त 212 शिक्षक 2018 में ही 12 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। इस दौरान महेश श्रीवास्तव, अभिषेक शर्मा, भीमसिंह यादव, विष्णु भार्गव, अवनेश रघुवंशी, रामबाबू रघुवंशी, संजय मोहन माथुर, महावीर जैन, माखन सिंह यादव, मनोज चौरसिया आदि जिला पदाधिकारी मौजूद थे।

कॉलेजों में 29 जून से होगी परीक्षा

597 परीक्षा केन्द्रों पर 4 लाख विद्यार्थी देंगे परीक्षा

स्टार समाचार | भोपाल

प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाए पेन-पेपर मोड पर 29 जून से 31 जुलाई के मध्य आयोजित होंगी।

इसके तहत 7 विश्वविद्यालयों में लगभग 4 लाख विद्यार्थी स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं देंगे। 597 परीक्षा केन्द्रों पर स्नातक अंतिम वर्ष के लगभग 3 लाख 4 हजार 853 विद्यार्थी तथा स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर के लगभग एक लाख विद्यार्थी आफलाइन परीक्षा में शामिल होंगे।

छह विवि में स्नातक स्तर की 25 %परीक्षा हो गई

राजन ने बताया कि रीवा विवि को छोड़ कर शेष 6 विवि में स्नातक स्तर की 25 प्रतिशत परीक्षा हो गई है। स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाएं किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन में परीक्षा केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष का अति. प्रभार सिंह को

जीएडी ने किए कई आईएएस व एसएएस अफसरों के तबादले

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

राज्य शासन ने कृषि उत्पादन आयुक्त केके सिंह को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ ही प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा है। इसी के साथ ही एक दिन पहले ही प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नत हुए डॉ. राजेश राजौरा को राजस्व मंडल के अध्यक्ष के समकक्ष घोषित किया गया है।

मीना को उपायुक्त मप्र पर्यटन का अतिरिक्त प्रभार

सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक से जारी आदेश के अनुसार अपर प्रबंध संचालक मप्र पर्यटन बोर्ड सोनिया मीना को उप सचिव पर्यटन विभाग के वर्तमान कर्तव्यों के साथ अस्थाई रूप से उपायुक्त मप्र पर्यटन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा है। इसीतरह राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) के अफसर अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल कमल सोलंकी को मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में मुख्य महाप्रबंधक बनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग पूल में पदस्थ अभिषेक दुबे को मप्र सड़क प्राधिकरण में मुख्य महाप्रबंधक बनाया गया है। अपर आयुक्त नगर निगम राजेश राठौर को संयुक्त कलेक्टर इंदौर, अनुकूल जैन को उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, शाश्वत सिंह मीना को अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल में पदस्थ किया गया है। राज्य शासन ने संयुक्त कलेक्टर देवास कैलाश चंद्र परते को संयुक्त कलेक्टर बैतूल तथा डिप्टी कलेक्टर नरसिंहपुर दिनेश सिंह तोमर को डिप्टी कलेक्टर सीहोर पदस्थ किया गया है।

माशिमं भोपाल से बोल रहा हूं, आपका बेटा फेल हो रहा है, पास करवाने के 5500 रु. लगेंगे, अकाउंट में ट्रांसफर करो

माशिमं भोपाल के नाम से निजी स्कूल के अभिभावकों को आ रहे फर्जी कॉल, थाने में शिकायत

भास्कर संवाददाता | खंडवा

पृथ्वीराज बात कर रहे हैं क्या। मैं भोपाल एमपी बोर्ड से बोल रहा हूं, आपका भानजा कम नंबर आने के कारण फेल हो रहा है। आप पास कराना चाहते हैं तो एक विषय के 5500 रुपए हमारे अकाउंट में डाल दें, हम पास कर देंगे।

इन दिनों ऐसे फोन कॉल्स सीबीएसई 10वीं कक्षा के छात्र व उनके अभिभावकों को किए जा रहे हैं। ऐसा ही कॉल माता चौक निवासी जसविंदर सिंग को सोमवार सुबह 10 बजे आया। कॉलर ने मोबाइल नंबर 8651340912 से फोन कर बताया कि वह भोपाल एमपी बोर्ड से बोल रहा है, आपके भानजे पृथ्वीराज ने एमपी बोर्ड से 10वीं की परीक्षा दी थी, जिसमें वह हिंदी व गणित में फेल हो रहा है, आप हमारे अकाउंट नंबर 31528954301 जो अजय बेहरा के नाम से है, उसमें 5500 रुपए प्रति विषय के हिसाब से ट्रांसफर कर दें, पैसा अकाउंट में आते ही हम उसे उत्तीर्ण कर देंगे। जसविंदर सिंग ने बताया उनका भानजा तो संत जोसफ में पढ़ता है और कॉलर ने बताया कि वह एमपी बोर्ड से है। ऐसे में शंका होने पर वह स्कूल गए और उन्होंने यह बात प्राचार्य को बताई। कोतवाली थाने में शिकायत करने गए।

कोचिंग संचालक इमरान परियानी ने बताया उनके छात्र प्रतीक सोनी के अभिभावक को भी फोन कर रुपयों की मांग की गई। अभिभावक शैलेंद्रसिंह चौहान ने बताया उनकी बेटी अनुष्का चौहान ने संत जोसफ स्कूल से 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है। उन्होंने बताया कि अभिभावकों के नंबर, बच्चों के नाम, स्कूल के नाम उनके पास कैसे आए। जेईई की परीक्षा में सारी जानकारी मांगते हैं, वहीं से जानकारी लीक हुई है। हम शिकायत करेंगे।

> *कुछ अभिभावकों ने मौखिक शिकायत की है। लिखित में करते हैं तो ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ हम केस दर्ज करेंगे। आमजन से विनती है कि ऐसी धोखाधड़ी में ना पड़ें, सावधानी बरतें।*
>
> **-विवेक सिंह,** पुलिस अधीक्षक

पढ़ाई का सवाल • जिन देशों ने स्कूल फिर खोलने का फैसला किया, वहां विरोध भी जारी

ब्रिटेन: पहले दिन ही कई स्कूल बंद, 50% अभिभावकों ने कहा- बच्चों को नहीं भेजेंगे

स्कूलों ने कहा- वे अभी क्लास चलाने के लिए तैयार नहीं

एजेंसी | लंदन

सरकार की मंजूरी के बावजूद ब्रिटेन में सोमवार को ज्यादातर प्राइमरी स्कूल नहीं खुले। करीब 50 फीसदी अभिभावक स्कूलों के सामने बच्चों को लेकर पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा कि वे सिर्फ यह बताने के लिए आए हैं कि अभी बच्चों को क्लास रूम में नहीं भेज सकते। उन्हें कोरोना फैलने का डर है। ज्यादातर अभिभावकों ने कहा कि स्कूल सितंबर के बाद ही खुलने चाहिए। अभिभावकों के संगठनों ने कहा कि 15 जून के बाद हालात देखने के बाद ही स्कूलों को खोलने का फैसला करना चाहिए था। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। इससे पहले देश की 13 काउंसिल ने स्कूल खोलने का विरोध किया था। ब्रिटेन के प्राइमरी स्कूलों में करीब 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं। कई स्कूलों ने कहा कि वे स्कूल खोलने की पूरी तैयारी नहीं कर सके हैं। कुछ स्कूलों ने क्लास रूम में छात्रों की संख्या कम कर दी है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। ब्रिटेन में 10 हफ्तों से स्कूल बंद थे। उधर, हाउसिंग सेक्रेटरी रॉबर्ट जेनरिक ने कहा है कि स्कूलों का खुलना बहुत जरूरी है। ब्रिटेन में अब तक 2,74,762 मामले आए हैं। जबकि 38,489 मौतें हुई हैं।

स्कूलों के गेट के सामने खड़े होकर फैसले का विरोध

तस्वीर ब्रिटेन की नॉरफोक काउंटी की है। यहां कुछ बच्चे अभिभावकों के साथ पहुंचे। हालांकि, स्कूल के भीतर नहीं गए।

द. अफ्रीका : सुरक्षा उपकरण कम, स्कूल खोलने का फैसला टाला

केपटाउन| दक्षिण अफ्रीका ने दो महीने बाद अनलॉक करते हुए पूजा स्थल, खदानें और फैक्ट्रियां दोबारा खोलने की अनुमति दी है, पर स्कूल खोलने का फैसला 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है। यहां शिक्षकों ने स्कूलों को खोलने का विरोध किया है। उनका कहना है कि स्कूलों में सुरक्षा उपकरण कम हैं। ऐसे में ये नहीं खोले जाने चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में 32,683 मामले आए हैं। जबकि 683 मौतें हुई हैं।

द. कोरिया : कोरोना का फैलाव बढ़ा तो 838 स्कूल फिर से बंद कर दिए

सियोल| दक्षिण कोरिया में स्कूल खुल गए थे, लेकिन कोरोना का फैलाव तेज होने के बाद 838 स्कूल फिर बंद कर दिए गए। ये ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखेंगे। देश में 20,902 स्कूल हैं। जो स्कूल खुल रहे हैं, वहां छात्रों के बीच प्लास्टिक बैरियर लगाए गए हैं। बच्चों को एक दूसरे के पास बैठकर खाना खाने की भी अनुमति नहीं है। दक्षिण कोरिया में 11,503 मामले आए हैं। जबकि 271 मौतें हुई हैं।

भारत: 2.13 लाख लोगों की याचिका, बोले- जल्द न खोले जाएं स्कूल

नई दिल्ली | भारत में 2.13 लाख से अधिक अभिभावकों ने स्कूलों को जल्द नहीं खोलने की मांग की है। इन लोगों ने एक ऐसी याचिका पर दस्तखत किए हैं, जिसमें कहा गया है कि जब तक कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार नहीं होता या इसके लिए टीका नहीं बन जाता, तब तक स्कूल नहीं खोलने चाहिए। सरकार ने घोषणा की थी कि सभी राज्यों में महामारी का आकलन और चर्चा करने के बाद जुलाई से स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को खोला जा सकता है। अभिभावकों ने कहा कि जुलाई में स्कूल खोलना सरकार का सबसे खराब फैसला होगा। यह आग से खेलने जैसा है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र ऑनलाइन जारी रहना चाहिए। अगर स्कूल दावा करते हैं कि वे ऑनलाइन पढ़ाकर अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर इसे बाकी शैक्षणिक वर्ष के लिए जारी रखना चाहिए। देशभर में 16 मार्च से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं।

29 से शुरू होंगी जीवाजी विवि की मुख्य परीक्षाएं

ग्वालियर, न.सं.

लॉकडाउन चार समाप्त होते ही जीवाजी विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं का मसौदा तैयार कर लिया है। विवि की रुकी हुई स्नातक अंतिम वर्ष की वार्षिक मुख्य परीक्षाएं 29 से शुरू होंगी। जबकि स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 30 जून से कराने की योजना बनाई गई है। परीक्षाओं में सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। छात्रों को एक मीटर की दूरी पर बैठाया जाएगा और उन्हें मास्क लगाकर अनिवार्य रूप से आना होगा। इस संबंध में विवि प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

कोरोना महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन की वजह से शैक्षणिक संस्थानों पर ताले पड़ गए थे। विवि की मार्च-अप्रैल में होने वाली वार्षिक मुख्य परीक्षाएं प्रभावित हुई। यह परीक्षाएं समय पर नहीं हो सकीं। अब लॉकडाउन चार समाप्त होने के साथ ही विवि की गतिविधियां शुरू हो गई। विवि प्रशासन ने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाकर रुके हुए काम करवाना शुरू कर दिया। जिसमें से पहली प्राथमिकता परीक्षाओं को दी गई। इसलिए अब विवि ने स्नातक व स्नात्कोत्तर की परीक्षाओं की तिथियां भी तय कर दी हैं। विवि परिक्षेत्र के करीब चार महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया जाएगा। इस संबंध में महाविद्यालयों से जानकारी मांगी गई है कि उनके यहां पर परीक्षा कराने के संबंध में क्या व्यवस्थाएं है। यदि वह परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है तो नजदीक के महाविद्यालय से चर्चा कर प्रस्ताव भेजें, ताकि वहां पर केन्द्र बनाया जा सके। छात्रों के एक मीटर की दूरी पर बैठाया जाएगा। विवि ने परीक्षाओं की तिथियां तय कर दी हैं। स्नातक अंतिम वर्ष की वार्षिक मुख्य परीक्षाएं 29 जून से शुरू होंगी। यह परीक्षाएं सुबह और दोपहर की पाली में कराई जाएंगी।

प्रदेश के सात विवि में चार लाख परीक्षार्थी देंगे परीक्षा: प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं पेन-पेपर मोड पर होंगी। सात विश्वविद्यालयों में लगभग चार लाख विद्यार्थी स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं देंगे। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने बताया कि कुल 597 परीक्षा केन्द्रों पर स्नातक अंतिम वर्ष के लगभग 3 लाख 4 हजार 853 विद्यार्थी तथा स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर के लगभग एक लाख विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा में शामिल होंगे।

इनका कहना है

"परीक्षाओं की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्नातक अंतिम वर्ष की मुख्य परीक्षाएं 29 और स्नातकोत्तर की 30 जून से प्रस्तावित हैं। इस संबंध में महाविद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।"

प्रो. आनंद मिश्रा
कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय

राजौरा एसीएस श्रम, निगम व टीएंडसीपी में भी तबादले

भोपाल| वर्ष 1990 कैडर के आईएएस अधिकारी राजेश राजौरा पदोन्नति के बाद अपर मुख्य सचिव(एसीएस) श्रम पदस्थ किए गए हैं। वे इसी विभाग में प्रमुख सचिव रहे। अपर मुख्य सचिव व पीईबी के चेयरमैन रहे प्रभांशु कमल के 31 मई को रिटायर होने के बाद एक पद रिक्त हुआ। इसी पद पर राजौरा अपर मुख्य सचिव बने। 30 जून को ट्राई के डायरेक्टर व अपर मुख्य सचिव पीसी मीणा रिटायर होंगे। इससे एक पद और रिक्त होगा, जिसमें 1990 बैच के ही आईएएस व गृह विभाग के प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा अपर मुख्य सचिव पद पर पदोन्नत होंगे। इधर, राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन आयुक्त केके सिंह को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

निगम के अपर आयुक्त सोलंकी व राठौड़ का ट्रांसफर

नाम	वर्तमान पदस्थापना	नई पदस्थापना
• कमल सोलंकी	अपर आयुक्त (ननि, भोपाल)	मुख्य महाप्रबंधक, एमपीआरआरडीए
• अभिषेक दुबे	जीएडी (पूल)	मुख्य महाप्रबंधक, मप्र, सड़क विकास निगम
• राजेश राठौड़	अपर आयुक्त (ननि भोपाल)	संयुक्त कलेक्टर, इंदौर
• अनुकूल जैन	जीएडी (पूल)	उप संचालक, स्वास्थ्य
• एसएस मीणा	अवर सचिव, जीएडी	अपर आयुक्त, ननि भोपाल

टीएंडसीपी...सावलकर फिर चीफ सिटी प्लानर बने

• विजय सावलकर	चीफ आर्किटेक्ट, बीडीए	चीफ सिटी प्लानर ननि भोपाल
• एसएस राठौर	चीफ सिटी प्लानर, (ननि भोपाल)	जिला कार्यालय, उज्जैन
• संजय मिश्रा	जिला कार्यालय, उज्जैन	जिला कार्यालय, भोपाल
• सुनीता सिंह	जिला कार्यालय, भोपाल	चीफ आर्किटेक्ट, हाउसिंग बोर्ड, भोपाल

एंकर स्टोरी आरोग्य सेतु ऐप की बढ़ रही लोकप्रियता, 13 दिन में जुड़े 5 करोड़ नए यूज़र्स

12 करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके हैं ऐप

जेएनएन, नई दिल्ली। आरोग्य सेतु ऐप 2 अप्रैल को लांच किया गया था। 2 महीने में इस ऐप के डाउनलोड्स की संख्या 12 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इस तरह यह भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए हेल्थ ऐप्स की फेहरिस्त में शामिल हो गया है। सरकार ने हाल ही में इस ऐप को एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ओपन सोर्स किया था। इसके बाद कुछ ही समय में ऐप ने 12 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीएमओ के ट्वीट में इसका जिक्र किया। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा, मुझे यकीन है कि आपने आरोग्य सेतु के बारे में सुना होगा। 12 करोड़ सेहत के लिए सजग लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इससे बहुत मदद मिली है।

कई क्षेत्रों में ऐप अनिवार्य

आरोग्य सेतु ऐप से महज 13 दिन में 5 करोड़ नए यूजर्स जुड़े हैं। सरकार ने कई क्षेत्रों में इस ऐप को अनिवार्य कर दिया है। कई दफ्तरों, रेल और हवाई यात्रा के दौरान इस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, इसकी अनिवार्यता पर विवाद भी हुआ है।

ऐसे इस्तेमाल करें आरोग्य सेतु ऐप

सबसे पहले यह ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर फोन में इंस्टॉल करना होगा। आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने के बाद पहली बार इसे ओपन करेंगे तो कुछ परमिशंस भी देनी होंगी। यह ऐप आपके मोबाइल नंबर, ब्लूटूथ और लोकेशन डेटा की मदद से पता करता है कि आप सुरक्षित हैं या फिर आप पर संक्रमण का खतरा है। आरोग्य सेतु ऐप इस्तेमाल करने के लिए ब्लूटूथ और जीपीएस का ऐक्सेस देने के बाद आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। इस नंबर पर आने वाले ओटीपी की मदद से आप खुद को वेरिफाई कर सकेंगे।

आपको अलर्ट करता है आरोग्य सेतु

आपके लोकेशन डिटेल्स और सोशल ग्राफ के आधार पर आरोग्य सेतु ऐप बताएगा कि आप कोरोना की लो-रिस्क या फिर हाई-रिस्क किस कैटिगरी में हैं। अगर आप हाई-रिस्क पर होंगे तो ऐप आपको अलर्ट करते हुए टेस्ट सेंटर विजिट करने की सलाह भी देगा। हालांकि, हाल ही में फ्रांस के एक हैकर ने दावा किया था कि ऐप से यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा है, जिस पर सरकार को सफाई देनी पड़ी थी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि ऐप का डेटा 30 दिनों में अपने आप हट जाता है। कुछ विशेष मामलों में ही डेटा लंबे समय तक रखा जाता है।

इंतजार खत्म; देश में आईं मानसून की पहली बौछारें

केरल में समय पर पहुंचा मानसून, उज्जैन में 22 जून तक देगा दस्तक

एजेंसी | कोच्चि

मानसून ने केरल में सोमवार को तय समय, यानी 1 जून को दस्तक दे दी। वहां अधिकांश इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। अब उम्मीद है कि मानसून देश के बाकी हिस्से में भी समय पर पहुंच जाएगा। मध्यप्रदेश में इसके 20 जून तक पहुंचने का अनुमान है। उज्जैन में 22 जून तक आ सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पूरे देश में मानसून 8 जुलाई तक पहुंच जाएगा। 41% संभावना है कि मानसून सामान्य रहेगा। जबकि, इस बात की केवल 5% आशंका है कि मानसून सामान्य से कम होगा। विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि मानसून (जून से सितंबर) में 102% बारिश होगी। इसमें 4% ज्यादा या कम की गुंजाइश है। यानी कम से कम 96% और अधिकतम 106% तक बारिश की संभावना है।

भोपाल में 20 जून, जयपुर में 29 जून को पहुंच सकता है

शहर	मानसून आएगा	विदाई
भोपाल	20 जून	3 अक्टूबर
रायपुर	5 जून	14 अक्टूबर
जयपुर	29 जून	23 सितंबर
पटना	16 जून	8 अक्टूबर
रांची	14 जून	9 अक्टूबर
अहमदाबाद	26 जून	28 सितंबर
मुंबई	11 जून	8 अक्टूबर
जालंधर	26 जून	21 सितंबर
हिसार	3 जुलाई	21 सितंबर
चंडीगढ़	28 जून	23 सितंबर
दिल्ली	27 जून	25 सितंबर
शिमला	22 जून	24 सितंबर

फोटोः अजीब कोमाची (मलप्पुरम, केरल)